an>

Title: Need to ban organisations promoting anti-national sentiments in the country.

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) ः पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित रामजस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प ने लोगों का ध्यान एक बार फिर से देश के उच्च शिक्षण-संस्थानों की तरफ केन्द्रित कर दिया है। जवाहर लाल नेहरू (जे.एन.यू.) में भारत की बर्बादी के नारों को बमुश्किल एक साल ही गुजरा था कि रामजस कॉलेज में भी वैसे ही नारे सुनने में आए। जाहिर है कि इससे बहस का बिन्दु फिर से राष्ट्रवाद और अभिव्यक्ति की आजादी पर टिक गया। 2014 से और खासतौर से पिछले साल से यह बहस बार-बार सतह पर उभर कर आती है और टकराव पैदा करती है। रामजस कॉलेज में भी यही हुआ। इस समूचे घटनाक्रम को इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे एबीवीपी द्वारा किसी सेमिनार को रोक दिया गया हो और देश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी लग गई हो। समझना कठिन है कि इसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है कि वही चंद संगठन और चेहरे हैदराबाद, एफ.टी.आई.आई. और जे.एन.यू. से लेकर हर जगह इस प्रकार के हंगामें में क्यों शामिल रहते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी दशकों से सशक्त है, लेकिन कभी भी वहां पर ऐसा हंगामा और पुलिस की मौजूदगी नहीं देखी गई। जे.एन.यू. में पिछले साल छात्र संघ चुनाव में ए.बी.वी.पी. की निश्चित जीत को रोकने के लिए सारी वामपंथी पार्टियों को महागठबंधन बनाना पड़ा था। इसके बावजूद वोट के शेयर से ए.बी.वी.पी. आज जे.एन.यू. का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। जे.एन.यू. या अपने अन्य गढ़ों में भारत विरोधी नारे या कश्मीर, मणिपुर अथवा बस्तर की आजादी के नारे बिल्कुल नए नहीं हैं। अन्तर बस इतना है कि आज इन नारों का सशक्त विरोध करने वाला संगठन भी मौजूद है। वामपंथी संगठन और बुद्धिजीवी आलोचना से बचने के लिए यह आड़ ले रहे हैं कि भुखमरी, जातिवाद और गरीबी से आजादी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर गौर करें वामपंथी विचारधारा के अनुसार भुखमरी, गरीबी आदि से आजादी तभी मिल सकती है जब भारत का अस्तित्व खत्म हो जाए। उनकी समझ से भारत का अस्तित्व ही दमनकारी है और उसी ने कश्मीरी, तमिल, आदिवासियों और अन्य राष्ट्रीयताओं का गुलाम बना रखा है। रामजस कॉलेज में भी वे कुछ ऐसी ही वकालत कर रहे थे।

अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि देश विरोधी नारे लगाने वाले संगठनों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया जाए।

-